प्रसार भारती
भारत का लोक सेवा प्रसारक
आकाशवाणीः क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवारः 10.02.2026, समयः 07.20

मुख्य समाचार :—

- उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने राज्य में कोडीन युक्त कफ सिरप के निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई।
- नैनीताल ज़िले में कैंचीधाम बायपास पर पन्द्रह जून तक हर हाल में यातायात शुरू करने के निर्देश।
- जन—जन की सरकार, जन—जन के द्वार अभियान जनसमस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बना। 31 हजार से अधिक लोगों की समस्याओं का किया गया निराकरण।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने को कहा।

रोक

उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने राज्य में कोडीन युक्त कफ सिरप के निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी है और संबंधित औषधियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई अवैध और घटिया औषधियों के खिलाफ अभियान के तहत की गई है।

निर्देश

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पन्द्रह जून तक नैनीताल ज़िले में कैंचीधाम बायपास पर हर हाल में यातायात शुरू करने के निर्देश दिए हैं। भीमताल में ज़िले के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि यदि बायपास पर बन रहे पुल के निर्माण में देरी की संभावना हो, तो अस्थायी बेली ब्रिज की व्यवस्था कर तय समय में सड़क चालू की जाए, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुगम और सुरक्षित यात्रा मिल सके।
विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पर्यटन मंत्री द्वारा 12 करोड़ 58 लाख रुपये की पांच योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इनमें लोक निर्माण विभाग की चार योजनाओं का शिलान्यास और एक योजना का लोकार्पण शामिल है। इस अवसर पर सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार विकास योजनाओं को धरातल पर उतार रही है और नैनीताल भी तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
बैठक में सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए श्री महाराज ने निर्देश दिए कि बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव प्राथमिकता से शासन को भेजे जाएं और भारी वाहनों के अनुरूप सड़कों का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने हॉटमिक्स कार्य में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए।

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने–अपने क्षेत्रों की समस्याओं और सुझावों से मंत्री को अवगत कराया। इस दौरान जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

सखी वन धन केंद्र

देहरादून ज़िले के सहसपुर ब्लॉक के नया गांव पेलियों, ग्राम पंचायत भूडी चकमनसा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सखी वन धन केन्द्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। सखी वन धन केन्द्र के माध्यम से बोकसा जनजाति से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस केन्द्र से कुल 55 महिलाएं जुड़ी हैं, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की सदस्य हैं। यहां महिलाएं गांव में उत्पादित साबुत मसालों का क्रय, सफाई, पिसाई और पैकिंग कर उन्हें बाजार में उपलब्ध कराएंगी।

इस पहल से महिलाओं की आय बढ़ने के साथ ही गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही किसानों को भी अपने उत्पाद बेचने का बेहतर अवसर मिलेगा, जिससे खेती के प्रति रुचि बढ़ेगी। केन्द्र के संचालन से महिलाओं के साथ–साथ उनके परिवारों और पूरे गांव के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

फ्लेवर ऑफ देवभूमि

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून स्थित लोक भवन में 'फ्लेवर ऑफ देवभूमि' पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में उत्तराखंड के पारंपरिक खान–पान, संस्कृति एवं जीवन–शैली को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों के साथ उनके स्वास्थ्य लाभों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पाद और व्यंजन स्वाद के साथ–साथ औषधीय गुणों से भी भरपूर हैं और वर्तमान समय में इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। आज लोग तेजी से जैविक उत्पादों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और उत्तराखण्ड इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

जन–जन की सरकार

राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा "जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार" अभियान प्रदेश में जनसमस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी जिलों में लगाए जा रहे शिविरों के माध्यम से लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

प्रदेशभर में अब तक कुल 597 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों में अब तक चार लाख 68 हजार से अधिक नागरिकों ने सहभागिता की है। केवल 8 फरवरी को आयोजित आठ शिविरों में 4 हजार 822 लोगों ने अपनी समस्याएं और आवेदन दर्ज कराए।

अभियान के अंतर्गत अब तक 46 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 31 हजार से ज्यादा का निस्तारण किया जा चुका है। शिविरों के माध्यम से विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए 66 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत अब तक दो लाख 60 हजार से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक, बैंकों और दूरसंचार विभाग के परामर्श से डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया—एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने डिजिटल धोखाधड़ी के माध्यम से 54 हजार करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी को डकैती बताया है। शीर्ष न्यायालय ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।

जलवायु परिवर्तन/शोध

उपग्रह आधारित अध्ययनों से उत्तराखंड की पहाड़ियों में वनस्पति क्षेत्र के लगातार सिकुड़ने के संकेत मिले हैं। हालिया शोध में बताया गया है कि हिमालयी क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं और बदलते तापमान, वर्षा के पैटर्न और बढ़ते प्रदूषण का सीधा असर यहां की वनस्पति पर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट—

सड़क निर्माण कार्य

देहरादून जिले के शिमला बायपास रोड पर सड़क खुदाई से आमजन को हो रही असुविधा और यातायात बाधा की शिकायतों पर प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्पष्ट हुआ कि शिमला बायपास मार्ग पर खुदाई उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) द्वारा की गई थी।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए सड़क की मरम्मत कार्य तत्काल कराया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि भविष्य में किसी भी सड़क खुदाई के बाद निर्धारित मानकों के अनुसार समयबद्ध रूप से रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण किया जाए, अन्यथा लापरवाही की स्थिति में संबंधित संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।